बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 232

# केजरीवाल की राजनीति

**राजधानी** नई दिल्ली में महिलाओं के नि:शुल्क सफर के लिए जारी किए गए गुलाबी रंग के बस टिकट के एक ओर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तस्वीर छपी है। उसके ऊपर उनका एक वक्तव्य छपा हुआ है: 'मैं चाहता हूं कि आप और आपका परिवार खूब तरक्की करें। जब महिलाएं आगे बढ़ेंगी, तभी देश आगे बढ़ेगा।' दिल्ली की 1.6 करोड़ की आबादी में से रोज तकरीबन 20 लाख महिलाएं सार्वजनिक बसों की सेवा लेती हैं। स्पष्ट है कि यह अभियान फरवरी में होने जा रहे दिल्ली विधानसभा की तैयारी है और यह हमें देश के लगभग 60,000 पेट्रोल पंपों पर लगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होर्डिंग की याद दिलाता है जिनमें वह आत्मतुष्ट मुस्कान के साथ हमारी ओर देख रहे हैं। होर्डिंग के नीचे कोने में एक महिला घरेलू गैस सिलिंडर पर मिली सब्सिडी के लिए उनका धन्यवाद कर रही है, मानो यह कोई निजी दरियादिली हो। गर्मियों में आम चुनाव के समय ये होर्डिंग हटाने पड़े थे लेकिन अब उनकी वापसी हो चुकी है।

आम आदमी पार्टी के केजरीवाल मोदी के राजनैतिक विकल्प हैं। कम से कम राजधानी में तो ऐसा ही है। परंतु उनमें कुछ समानताएं भी हैं। दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा शुरू की है जिसमें मथुरा-वृंदावन, ऋषिकेश-हरिद्वार, आनंदपुर साहिब और अजमेर शरीफ आदि की तीर्थ यात्रा का पूरा व्यय सरकार उठाती है। आप सोच सकते हैं कि धार्मिक तीर्थ यात्राएं आयोजित करना एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का काम नहीं है और यदि मोदी भी ऐसा कुछ करते तो विरोध की झड़ी लग जाती। बल्कि कांग्रेस ने तो वर्षों तक हज सब्सिडी पर काफी पैसा खर्च किया था। मोदी सरकार ने पिछले साल उसे बंद कर दिया। इसके बावजूद हम सर्व धर्म सद्भाव वाले देश हैं, न कि पश्चिमी शैली के कट्टर धर्मनिरपेक्ष। ऐसे में सब चलता है।

इसके बाद विचार करते हैं लोकलुभावन कदमों पर। मोदी सरकार नि:शुल्क शौचालय, नि:शुल्क दवा बीमा और किसानों को धनराशि की पेशकश कर रही है। केजरीवाल नि:शुल्क बिजली तथा बस और मेट्रो की नि:शुल्क सवारी की पेशकश कर रहे हैं। मोदी यह नहीं पूछते कि दिवालिया होने के कगार पर खड़ी सरकार पैसे कहां से जुटाएगी और केजरीवाल जो उस राजधानी क्षेत्र के मुखिया हैं जिसकी प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत के तीन गुना है, वह यह नहीं पूछते कि ऐसी रियायतों की जरूरत ही क्या है? मुद्रास्फीति के बावजूद दिल्ली में संपत्ति कर बीते 15 वर्षों से एक समान है। दोनों नेताओं को बढ़ाचढ़ाकर दावे करना सुहाता है। पांच साल से हम सुन रहे हैं कि 1,000 मोहल्ला क्लीनिक बनाए जा रहे हैं लेकिन कुल आंकड़ा 200 से कम है। यह दावा कुछ वैसा ही है जैसा कि देश के खुले में शौच से मुक्त होने का दावा या आधार की मदद से सरकारी धन की भारी बचत। जिन सरकारी बसों में महिलाओं को नि:शुल्क सफर कराया जा रहा है उनकी बात करें तो 2010 से उनके बेड़े में एक भी नई बस नहीं जुड़ी है और मामला 5,000 बसों पर अटका हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार के पास उन्हें पार्क करने की व्यवस्था नहीं है।

काम करने की शैली की बात करें तो मोदी ने एक काडर वाले राजनैतिक दल को ऐसी पार्टी में बदल दिया है जहां सूर्योदय से सूर्यास्त तक उनका स्तुतिगान किया जाता है। केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक व्यापक आंदोलन और एक राजनीतिक संस्कृति को एक ऐसे दल में बदल दिया है जहां उनकी अबाध पकड़ है।

संक्षेप में कहें तो केजरीवाल ठीक उस पैकेज की तरह हैं जिसकी पेशकश मोदी करते हैं: लगातार अपना कद मजबूत करना, एक के बाद एक पूरे पन्ने के विज्ञापनों के साथ व्यक्तिगत छवि निर्माण, सब्सिडी वाली लोकलुभावन योजनाएं, धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों का परित्याग, बढ़चढ़े दावे और निरंकुश नेतृत्व। क्या अत्यंत सावधानीपूर्वक किए जा रहे इस अनुकरण के पीछे कोई दलील है? शायद, क्योंकि पिछले चुनाव के समय केजरीवाल ने कहा था कि उनके मतदाता वही हैं जो भाजपा के हैं।

यद्यपि दोनों में एक अंतर है। भाजपा की कट्टर सांप्रदायिकता आप में नहीं दिखती। यहां पहलू खान या अखलाक की हत्या जैसी वारदात नहीं होतीं। शायद इसीलिए मुस्लिम आप के साथ सुरक्षित महसूस करते हैं हालांकि विडंबना ही है कि दिल्ली की पुलिस अमित शाह के नियंत्रण में है। एक और महत्त्वपूर्ण बात यह है कि जहां भाजपा के शिक्षा कार्यक्रम में नेहरू को इतिहास की किताबों से निकाल बाहर करने की परियोजना सी चल रही है, वहीं आप ने सरकारी विद्यालयों में शिक्षा सुधार पर ध्यान केंद्रित किया है। इस अंतर का स्वागत किया जाना चाहिए।

साप्ताहिक मंथन

टी. एन. नाइनन

बिनय सिन्हा

# दुनिया का अगला शक्ति केंद्र बनेगा भारत?

वैश्विक शक्ति के नए केंद्र के रूप में उभरने के लिए भारत को अपनी क्षमताओं और संसाधनों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करना होगा। इसी से वह चीन के बरक्स खड़ा हो सकता है। बता रहे हैं **श्याम सरन**

इतिहासकार विलियम मैकनील ने शक्ति के चरित्र और निष्पक्षता एवं नैतिकता के साथ उसके संबंधों की व्याख्या कुछ इस तरह की है: 'इसकी संभावना बेहद कम दिखती है कि ताकत को संगठित करने और अमल में लाने के लिए मानव क्षमताओं का हालिया एवं संभावित विस्तार इसके उपयोग को लेकर हिचक का स्थायी भाव रखेगा। संक्षेप में, शक्ति खुद को सशक्त बनाने के लिए शक्ति के कमजोर केंद्र बनाती है या शक्ति के विरोधी केंद्रों को प्रोत्साहित करती है। मानवजाति के संपूर्ण इतिहास में यही तथ्य प्रभावी रहा है।'

यह अंतरराष्ट्रीय संबंधों के यथार्थवादी मत को परिलक्षित करता है जिसमें कोई भी नैतिक आश्रय नगण्य है लेकिन यह मौजूदा भू-राजनीतिक वास्तविकता को बखूबी दर्शाता है। एक अग्रणी ताकत बनने की आकांक्षा रखने वाला भारत भी मौजूदा एवं संभावित शक्ति पर अपना दांव लगा रहा है। यह खुद से अधिक ताकतवर निकाय द्वारा 'निगल' लिए जाने की संभावना को नकारता है। लेकिन क्या उसे शक्ति के प्रतिद्वंद्वी केंद्र के तौर पर उभरने के लिए प्रेरित किया जाएगा?

मैकनील ने यह भी बताया है कि एक स्थापित निकाय से एक आकांक्षी निकाय को ताकत का हस्तांतरण किस तरह हो सकता है? वह कहते हैं, 'कोई भी जनसंख्या धरती पर कहीं भी मौजूद सबसे कारगर एवं ताकतवर साधनों का उपयोग किए बगैर बाकी दुनिया को पीछे नहीं छोड़ सकती है। परिभाषा के मुताबिक ऐसे साधन धन एवं शक्ति के वैश्विक केंद्रों में ही स्थित होते हैं, वे कहीं भी हो सकते हैं। इस तरह वैश्विक नेतृत्व में किसी भी भौगोलिक विस्थापन की प्रस्तावना उच्चतम प्रबल कौशल के पूर्ववर्ती स्थापित केंद्रों से सफलतापूर्वक उधार ली जानी चाहिए।'

इतिहास में इस अवधारणा के कई उदाहरण मौजूद हैं। रोमन साम्राज्य ने शीर्ष तक के अपने सफर में ग्रीक सभ्यता से काफी कुछ उधार लिया था। इसी तरह अरबों ने भी अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए मध्य एशियाई और फारसी समुदायों के उन्नत ज्ञान-विज्ञान का बखूबी इस्तेमाल किया। फारसी समुदाय ने भी गणित, खगोलशास्त्र और चिकित्सा विज्ञान में भारतीय एवं चीनी लोगों से काफी कुछ सीखा था। हाल के दौर में हम अमेरिकी लोगों को एक सशक्त एवं उन्नत अर्थव्यवस्था का निर्माण करते हुए देखते हैं जिन्होंने ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय देशों में औद्योगिक क्रांति के दौरान विकसित तकनीकों एवं कौशल को अपनाते हुए ऐसा किया। मीजी काल के जापान ने भी यही प्रक्रिया अपनाई थी। लेकिन इसका सबसे नया और जबरदस्त उदाहरण चीन है जो एक महान शक्ति के रूप में उभरकर सामने आया है। सुधारों एवं खुलेपन के चार दशकों में चीन ने उन्नत पश्चिमी ज्ञान एवं तकनीकों को किसी विशाल स्पंज की तरह सोख लिया है। इस दौरान चीन विनम्र रहने के साथ सीखने और उद्यम के भी लिए तैयार रहा है। यही तंग श्याओ फिंग के मशहूर कथन 'अपनी क्षमताएं छिपाकर रखो और अपने लिए वक्त हासिल करो' का सही मतलब भी था। 'भीख मांगो, उधार मांगो और चोरी करो' की इस रणनीति का मिलाजुला नतीजा यह हुआ है कि चीन एक विश्वसनीय आर्थिक एवं तकनीकी शक्ति के तौर पर उभरकर सामने आया है। मैकनील के शब्दों में, अटलांटिक-पार से प्रशांत-पार की तरफ शक्ति का भौगोलिक विस्थापन जारी है और इसके केंद्र में चीन है जो प्रतिस्पर्द्धी केंद्र है।

शक्ति के इस विस्थापन को एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से भी समझा जा सकता है। यह ऐसे प्रक्षेपण-पथ में घटित होता है जो अतिव्याप्त हो रहे तीन चरणों से परिभाषित किया जाता है। पहले चरण में देश शक्ति के अग्रणी केंद्रों से ज्ञान एवं उन्नत तकनीकें उधार लेते हैं और उन्हें अपना लेते हैं। उसके बाद समावेशन का दौर होता है जब उधार की तकनीकों एवं ज्ञान में वे महारत हासिल कर उन्हें अपना बना लेते हैं। तीसरे एवं अंतिम चरण में शक्ति का उभरता केंद्र अधिक स्वायत्त ढंग से नए तरह के ज्ञान एवं तकनीकों को जन्म देने लायक हो जाता है। उस समय शक्ति का भौगोलिक विस्थापन वास्तविक आकार लेने लगता है और एक स्थापित केंद्र या केंद्रों और उदीयमान प्रतिद्वंद्वी के बीच प्रतिस्पर्द्धा काफी मुखर होती है।

सवाल है कि चीन इस समय किस दौर से गुजर रहा है? वह शायद दूसरे दौर से तीसरे दौर की तरफ बढ़ रहा है। इसके उलट भारत अभी पहले चरण से दूसरे चरण की तरफ ही जा रहा है। चीन पहले से ही कृत्रिम मेधा, रोबोटिक्स और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी उच्च तकनीकों में अमेरिका से मुकाबला कर रहा है। वहीं भारत इस दौड़ में अभी बहुत मायने नहीं रखता है। यह सच है कि भारत के पास भी अंतरिक्ष कार्यक्रम जैसे विशेषज्ञता वाले कुछ क्षेत्र हैं जिससे गर्व पैदा होना सही भी है। लेकिन उत्कृष्टता के इन केंद्रों को अभी उत्कृष्टता के महाद्वीप बनना होगा, अन्यथा वे अपने आसपास के मध्यम दर्जे के सागर में ही डूब सकते हैं।

अगर चीन के अनुभव से हमें कोई सबक सीखना है तो वह यही है कि उच्च तकनीकों एवं ज्ञान को हरसंभव जगह से आत्मसात करने के साथ ही विनम्र एवं शालीन बने रहें। खास तौर पर ऐसे युग में जब वृद्धि का प्रमुख चालक तकनीक ही है और भविष्य के सफल समाज ज्ञानपरक समाज ही होंगे।

भू-राजनीतिक कारक शक्ति के ऐसे प्रतिद्वंद्वी केंद्र के रूप में भारत के उभार का समर्थन करते हैं जो बड़ी शक्तियों के साथ प्रतिस्पर्द्धा, सह-अस्तित्व एवं सामंजस्य कायम रख सकता है। धन-दौलत और ताकत के स्थापित केंद्र अब भी अमेरिका, यूरोप और जापान ही हैं, लेकिन उनकी महत्ता थोड़ी कम हुई है। चीन के उदय को वे अपनी पुरानी महत्ता के लिए खतरा पैदा होने के तौर पर देखते हैं। स्थापित शक्तियों की नजर में भारत का भू-राजनीतिक मूल्य ऐसे अकेले देश के रूप में है जो एक भरोसेमंद ताकत बनने के लिए जरूरी क्षमताएं और संसाधन रखता है जिससे वह उभरते वैश्विक व्यवस्था में चीन को दबदबे वाली भूमिका निभाने से रोक सके। भारत का अपनी असीम संभावनाओं को पूरा करना इन शक्तियों के हित में भी है। विवेकपूर्ण उपयोग से भारत को पूंजी और प्रौद्योगिकी का बड़ा आधार बनाया जा सकता है जिससे वह वृद्धि की तीव्र रफ्तार कायम रख सकता है। एक जीवंत एवं बहुलवादी लोकतंत्र के रूप में भारत अपने अधिक ताकतवर साझेदारों के साथ राजनीतिक मूल्य भी साझा करता है और यह एक लाभ की स्थिति है।

भारत के लोगों की सर्वव्यापी मनोदशा एवं गहरी विविधता से निपटने की उनकी क्षमता एक वैश्वीकृत हो रहे विश्व से निपटने के लिए सभ्यता के बेमिसाल साधन हैं। लेकिन इन साधनों का फायदा उठाने के लिए कहीं अधिक विनम्रता एवं सब-कुछ जानने के बजाय सीखने की ललक जरूरी होगी। अतीत के सुनहरे स्तंभों का बार-बार जिक्र करने से मस्तिष्क एक विलक्षण भविष्य के लिए नहीं तैयार होता है।

हम अपने इतिहास के ऐसे दुर्लभ दौर में हैं जब सत्तारूढ़ राजनीतिक व्यवस्था के पास अभूतपूर्व राजनीतिक पूंजी है और एक करिश्माई एवं महत्त्वाकांक्षी नेता उसकी अगुआई करता है। हालांकि ये संसाधन जल्दी नष्ट होने वाले भी हैं लिहाजा मुश्किल चयन के लिए उन्हें संभालना होगा। ये चयन ही एक महान शक्ति की हैसियत हासिल करने का हमारा रास्ता निर्धारित करेगा। जैसा कि लोगों के साथ होता है, राष्ट्रों के समक्ष उत्पन्न होने वाले अवसरों की भी संक्षिप्त जीवन अवधि होती है। वे उस समय तक हमारा इंतजार नहीं करते रहेंगे जब हम खुद को उसके लिए तैयार समझें। दुनिया आगे बढ़ रही है और भारत को या तो इस प्रगति वलय से आगे रहना होगा या फिर सीमित विकल्पों वाले भविष्य से ही संतोष करना होगा।

*(लेखक पूर्व विदेश सचिव एवं सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के सीनियर फेलो हैं)*

# श्रीलंका के राष्ट्रपति चुनाव भारत के लिहाज से अहम

सियासी हलचल

आदिति फडणीस

**अब** से कुछ घंटों के बाद श्रीलंका को नया राष्ट्रपति मिल जाएगा जो इस पड़ोसी देश का आठवां कार्यकारी प्रमुख होगा। वर्ष 2015 में एक अविश्वसनीय गठजोड़ तैयार हुआ था जिसमें वामपंथी रुझान वाली श्रीलंका फ्रीडम पार्टी (एसएलएफपी) और मुक्त बाजार की समर्थक यूनाइटेड नैशनल पार्टी (यूएनपी) जैसे विरोधी मत वाले दल भी शामिल थे। इस गठजोड़ ने तत्कालीन राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे की अगुआई वाली श्रीलंका पीपुल्स पार्टी (एसएलपीपी) को हरा दिया था। मौजूदा राष्ट्रपति मैत्रीपाल श्रीसेना के नेतृत्व वाले इस गठजोड़ को प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे का भी समर्थन हासिल था। गठजोड़ ने मिलकर पहली नैशनल यूनिटी सरकार (एनयूजी) का गठन किया था।

हालांकि दो साल पहले इस गठजोड़ की गांठें खुलनी शुरू हो गई थीं। यह तनातनी एवं सत्ता संघर्ष उस समय चरम पर पहुंच गया जब श्रीसेना ने 2018 में एक तरह का संवैधानिक तख्तापलट करते हुए प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे को बर्खास्त कर दिया और उनकी जगह पर राजपक्षे को नया प्रधानमंत्री बना दिया। आखिर में सर्वोच्च अदालत के दखल के बाद विक्रमसिंघे को दिसंबर 2018 में प्रधानमंत्री पद पर बहाल किया जा सका। लेकिन श्रीलंका के राष्ट्राध्यक्ष एवं शासनाध्यक्ष के संघर्षपूर्ण संबंधों से शासन पूरी तरह पंगु हो चुका है और गत 21 अप्रैल को ईस्टर के दिन हुए आतंकी हमलों के पीछे भी यही मुख्य कारण रहा है। श्रीलंका में 2009 के बाद हुए इस पहले हमले ने एक बार फिर यहां आंतरिक संघर्ष छिड़ने की आशंका पैदा कर दी। हालत यह है कि इस भीषण बम धमाके की जांच के लिए राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री दोनों ने अलग-अलग आदेश जारी किए थे।

श्रीसेना और विक्रमसिंघे के बीच की खाई उस समय गहरी हो गई जब राष्ट्रपति ने रक्षा सचिव से कहा कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठकों में आमंत्रित न किया जाए। पूर्व रक्षा सचिव कपिला वैद्यरत्ने ने हाल ही में संसदीय आयोग के समक्ष अपनी गवाही में इसकी पुष्टि भी की है। राजनीतिक अस्थिरता का असर अर्थव्यवस्था को भी उठाना पड़ा है। बम धमाकों के बाद पर्यटन गतिविधियां सुस्त पड़ने से श्रीलंका को करीब 20 अरब रुपये का नुकसान झेलना पड़ा है।

राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के बीच का राजनीतिक साहचर्य असरदार नहीं हो पाया है। राजपक्षे अपने लाभ के लिए अपने सर्वशक्तिमान कार्यालय का इस्तेमाल करने वाले आखिरी राष्ट्रपति थे। उन्होंने गृहयुद्ध तो जीत लिया लेकिन चीन के साथ गलबहियां कर पश्चिमी देशों एवं भारत के साथ अपने रिश्तों को तल्ख कर लिया।

राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया खत्म होते ही यह राजनीतिक गतिरोध टूटने के आसार हैं। यूएनपी की अगुआई वाले गठबंधन नैशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट के एजेंडे में राष्ट्रीय सुरक्षा, लोकतंत्र एवं अर्थव्यवस्था है। इस गठबंधन की तरफ से आवासीय एवं निर्माण मंत्री सजित प्रेमदासा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाए गए हैं। वह पूर्व राष्ट्रपति रणसिंघे प्रेमदासा के बेटे हैं जिनकी लिट्टे विद्रोहियों ने हत्या कर दी थी। अगर सजित इस चुनाव में जीत जाते हैं तो पिता के बाद पुत्र के भी श्रीलंकाई राष्ट्रपति बनने का एक दृष्टांत होगा।

वहीं फरवरी 2018 में संपन्न स्थानीय निकाय चुनावों में बड़ी जीत दर्ज करने वाली एसएलपीपी जोश से भरी हुई है। राजपक्षे के छोटे भाई गोताबया राजपक्षे को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जाना पूर्वविदित ही था। अपने बड़े भाई की ही तरह गोताबया (गोता के नाम से लोकप्रिय) भी एक मजबूत एवं निष्ठुर नेता माने जाते हैं। उन्हें तमिल विद्रोहियों के खिलाफ लड़ाई में अहम भूमिका के लिए याद किया जाता है। श्रीलंकाई सेना में कर्नल रह चुके गोता निर्णायक संघर्ष के दौरान रक्षा सचिव के पद पर तैनात थे। भले ही वह श्रीलंका में सजित की तुलना में अधिक चर्चित हैं लेकिन उन पर जंग से जुड़े बोझ भी चस्पा हैं। लेकिन सिंहल बौद्ध समुदाय का समर्थन और एक सख्त प्रशासक की उनकी छवि गोता के पक्ष में जाती है। हालांकि उत्तरी एवं पूर्वी इलाकों में उन्हें निराशा हाथ लग सकती है जहां अल्पसंख्यकों का वर्चस्व है।

इसके उलट, सजित को श्रीलंका के आकांक्षावान युवा एक संभावित अच्छे प्रशासक के रूप में देखते हैं। वैसे उन पर भी अपनी पार्टी के पिछले कर्मों का बोझ है जिसमें मौजूदा आर्थिक समस्याओं का ठीकरा भी शामिल है।

ईस्टर पर धमाकों से उपजे हालात से सही तरीके से नहीं निपट पाना सत्तारूढ़ गठजोड़ पर भारी पड़ सकता है। गोता अगर चुनाव जीत जाते हैं तो वह इसी मुद्दे को आधार बनाकर देश की खुफिया एवं आतंकवाद-रोधी व्यवस्था का पुनर्गठन कर सकते हैं। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के अलावा भी राष्ट्रीय हित के लिए बहुत कुछ है।

वर्ष 2014-15 में महिंदा राजपक्षे को सत्ता से हटाने की अंतरराष्ट्रीय मुहिम में भारत की भी भूमिका रही थी। दरअसल चीन, पाकिस्तान, रूस, लीबिया एवं उत्तर कोरिया जैसे देशों के साथ महिंदा की नजदीकी असहज करती थी। महिंदा के राष्ट्रपति काल में ही चीन ने दक्षिण एवं मध्य श्रीलंका में अपना प्रभाव फैलाया था। बंदरगाहों, हवाईअड्डों और एक्सप्रेस राजमार्गों के अलावा चीन श्रीलंका में एक वाणिज्यिक शहर के विकास से भी जुड़ा था। इसके अलावा दोनों देशों के बीच राजनीतिक एवं रक्षा सहयोग भी मजबूत हुए थे। उनके कार्यकाल में ही चीन की पनडुब्बी पहली बार कोलंबो के तट पर पहुंची थी। चीन की महत्त्वाकांक्षी बेल्ट एवं रोड परियोजना में फंस चुके श्रीलंका को अपने हम्बनटोटा बंदरगाह को 99 वर्षों और प्रस्तावित कोलंबो पोर्ट सिटी कॉम्प्लेक्स को 90 वर्षों के लिए चीन के सुपुर्द करना है।

यूएनपी सरकार के कार्यकाल में श्रीलंका के भीतर चीन की भूमिका एक हद तक काबू में रही है। वहीं पिछले पांच वर्षों से सत्ता से बाहर राजपक्षे की जीत चीन को सामरिक बढ़त दे देगी।

## कानाफूसी

### भ्रष्टाचार पर आर-पार

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जिन्हें 2017 में प्रदेश के मुख्यमंत्री पद का तगड़ा दावेदार माना जा रहा था, अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर कहा है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण में बहुत बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हो रही हैं। योगी आदित्यनाथ के पास उत्तर प्रदेश आवास एवं शहरी नियोजन मंत्रालय भी है। ऐसे में वह लखनऊ विकास प्राधिकरण समेत तमाम विकास प्राधिकरणों के मुखिया भी हैं। मौर्य ने अपने पत्र में आरोप लगाया है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण और निजी बिल्डरों तथा ठेकेदारों के बीच शहर की प्रमुख आवासीय और बुनियादी परियोजनाओं को लेकर गठजोड़ है। आदित्यनाथ अफसरशाही से भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करते रहे हैं।

### सुर्खियों में अफसरशाही

मध्य प्रदेश में कुछ दिन पहले वायरल हुई एक वीडियो क्लिप ने मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार को शर्मिंदा कर दिया। इस वीडियो में देवास नगर निगम आयुक्त संजना जैन को लोक निर्माण विभाग के मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के पैर छूते हुए देखा जा सकता है। वीडियो उस समय का है जब वर्मा गुरुपर्व के अवसर पर देवास के एक गुरुद्वारे में पहुंचे थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष वृजेश लूणावत ने यह वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा, 'यह नया मध्य प्रदेश है। अफसरशाही मंत्री के चरणों में है।' यह पहला मौका नहीं है जब मध्य प्रदेश के किसी अफसरशाह का नाम गलत वजह से सुर्खियों में आया। सन 2018 में मंडला जिले की तत्कालीन कलेक्टर सूफिया फारुकी ने शंकराचार्य एकात्मक यात्रा के अवसर पर संत आदि शंकराचार्य की चरण-पादुका अपने माथे पर रखकर कुछ दूरी तय की थी। उस वक्त भाजपा सत्ता में थी। तब पार्टी ने उनकी फोटो को ट्वीट किया था जबकि उस समय की विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने इल्जाम लगाया था कि भाजपा अफसरशाहों का इस्तेमाल राजनीतिक हित के लिए कर रही है।

*सज्जन सिंह वर्मा*

## आपका पक्ष

### शिक्षण संस्थानों की फीस कम हो

दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। जेएनयू प्रसाशन ने हॉस्टल फीस 10 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये तथा 20 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये करने का निर्णय लिया था। इस निर्णय के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन कई दिनों से जारी था। जेएनयू में दीक्षांत समारोह के दिन छात्रों का विरोध प्रदर्शन बढ़ा गया। इस समारोह में उपराष्ट्रपति आने वाले थे। दीक्षांत समारोह के दिन छात्रों के उग्र प्रदर्शन को देखते हुए पानी की बौछार का इस्तेमाल भी किया गया। बाद में मानव संसाधन मंत्रालय ने बढ़ी हुई फीस में आंशिक बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया। इसके बाद 10 रुपये के हॉस्टल फीस को 100 रुपये और 20 रुपये के बदले 200 रुपये तय किया गया। सवाल यह है कि क्या देश के शिक्षण संस्थानों में हॉस्टल फीस एक जैसी है या उन शिक्षण संस्थानों में फीस घटाने के लिए विरोध प्रदर्शन किए गए हों। विश्वविद्यालय अनुदान कोष (यूजीसी) विश्वविद्यालयों को राशि देती है तथा इसके दिशानिर्देश में विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्यक्रम चलते हैं। ऐसे में पूरे देश में शिक्षण संस्थानों में फीस एक जैसी क्यों नहीं हो। जेएनयू कैंपस में ही भारतीय जनसंचार संस्थान स्थित है। यहां नौ महीने का पाठ्यक्रम होता है तथा यहां हॉस्टल फीस हर माह करीब 3,500 रुपये तथा मेस फीस करीब 3,000 रुपये प्रति माह है। यहां हॉस्टल फीस जेएनयू के मुकाबले सैकड़ों गुना अधिक है। इसकी फीस में कमी करने के लिए कभी जेएनयू के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया हो ऐसी कोई खबर नहीं है। हालांकि यहां छात्रों को हॉस्टल दिलाने के लिए जेएनयू कुछ छात्र विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए हों। बहरहाल शिक्षण संस्थानों में फीस एक जैसी होनी चाहिए जिससे गरीब छात्रों को भी उचित अवसर मिल सके।

*राजेश कुमार, नई दिल्ली*

**जेएनयू के छात्र हॉस्टल फीस में की गई बढ़ोतरी का विरोध कर रहे हैं** *-पीटीआई*

### अपने भविष्य के लिए लगाएं पेड़-पौधे

दिल्ली में पिछले कई दिनों से प्रदूषण खतरनाक स्तर पर है जिसके कारण स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। दिल्ली सरकार सम-विषम योजना चला रही है। पड़ोसी राज्यों में किसानों को पराली नहीं जलाने के लिए कहा जा रहा है। दिल्ली में पानी का छिड़काव किया जा रहा है। अदालत प्रदूषण को देखते हुए कड़े दिशानिर्देश जारी कर रहा है। दिल्ली-एनसीआर में निर्माण कार्य बंद है। इतनी सारी कवायदों के बाद भी प्रदूषण नहीं हो रहा है। लोग दूसरी जगह जाने को मजबूर हो रहे हैं। लोगों को पेड़ पौधे लगाने होंगे जिससे प्रदूषण कम हो सके। यह समय अपने भविष्य को संभालने का है जिसमें हर लोगों को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी।

*कोमल सिंह, नोएडा*

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।